



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 25, 1939 शक सम्वत्) [संख्या-50

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	855-862	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	729-752	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	167-168	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-02

विज्ञप्ति/नियुक्ति

14 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 797/XLI-1/17/12/प्रशि/2017-प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप पल्लवी को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी में प्रधानाचार्य श्रेणी-02, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा-2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त/तैनात करते हुए, दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य श्रेणी-02 की सेवाएँ "उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण (श्रम विभाग) सेवा नियमावली, 1981" के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो समय-समय पर द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन, आरक्षित श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य/रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(2.2) संबंधित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रधानाचार्य श्रेणी-02 के पद पर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थान में सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए, शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. तैनाती स्थल/संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण-पत्र निदेशक, प्रशिक्षण के माध्यम से शासन में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी:-

(3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण-पत्र।

(3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

(3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा-पत्र।

(3.4) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ-पत्र।

(3.5) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने का प्रमाण-पत्र।

(3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधित न हों, के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

(3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति।

(3.8) लिखित रूप से एक "UNDER TAKING" कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्राग्वृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो स्वतः नियुक्ति निरस्त समझी जाय।

(3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण-पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

4. अतः संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5. उक्त नियुक्तियाँ मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 158/2017, प्रमोद कुमार बेन्जवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका सं० 271/2017 शिप्रा थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1

विज्ञप्ति

17 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 1972/XLI-1/2017-100/2017-प्राविधिक शिक्षा विभाग के श्रेणी 'क' के निम्नलिखित कार्मिक उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात् वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 56(क) के प्राविधानानुसार सेवानिवृत्त हो जायेंगे:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	जन्मतिथि	पदनाम/संस्था का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री उमेश प्रसाद	20.01.1958	प्रधानाचार्य/रा०पा०, उत्तरकाशी	31.01.2018
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	10.01.1958	विभागाध्यक्ष, फार्मसी/रा०पा०, श्रीनगर (गढ़वाल)	31.01.2018

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

कार्मिक अनुभाग-4

विज्ञप्ति/नियुक्ति

10 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 387/XXX(4)/2017-04(3)/2017-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2015 के आधार पर चयनित एवं उनके पत्रांक 462/07/ई-2/CJ-JD/2015-16, दिनांक 16 मार्च, 2017 एवं पत्रांक 04/10/ई-2/CJ-JD/2015-16, दिनांक 06 अप्रैल, 2017 द्वारा की गई संस्तुति तथा इस सम्बन्ध में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 4225/XIII-d-1/Admin.A/2014, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के

पद पर वेतनमान ₹ 27,700-770-33,090-920-40,450-1080-44,770 में, नियुक्त किये जाने तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	नाम अभ्यर्थी	तैनाती स्थल
1	2	3
1.	श्री भूपेन्द्र सिंह शाह, द्वारा श्री पी० एस० शाह, म० सं०-38A/1, इन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून-248001	देहरादून
2.	सुश्री मीनाक्षी दूबे, P-III, 38, पूल्ड हाउस कॉलोनी, रोशनाबाद, हरिद्वार-249404	रुधमसिंह नगर
3.	सुश्री भावना पाण्डे, ग्राम-तल्ला सीमा, पो०ऑ०-शिशुआ, तहसील-रानीखेत, जिला अल्मोड़ा-263601	नैनीताल
4.	श्री विवेक सिंह राणा, निकट प्रताप नर्सरी, पंडितवाडी, देहरादून-248001	पौड़ी गढ़वाल
5.	सुश्री शिखा भण्डारी, P-II/26, यमुना कॉलोनी, देहरादून-248001	देहरादून
6.	श्री रिजवान अन्सारी, ग्राम-बसेडी खादर, पो०-लक्सर, जिला हरिद्वार-247663	देहरादून
7.	सुश्री कंचन चौधरी, 12/2, किशनपुर, राजपुर रोड, देहरादून-248009	हरिद्वार
8.	सुश्री शालिनी दादर, पुष्पराज भवन, सुखताल, मल्लीताल, नैनीताल-263001	रुधमसिंह नगर
9.	सुश्री निशा देवी, ग्राम-प्रतापपुर, पो०-खानपुर-बहमपुर (रायसी), तहसील-लक्सर, जिला हरिद्वार-247671	देहरादून
10.	श्री रोहित जोशी, मकान नं०-117, लेन नं०-8, विजय पार्क एक्सटेंशन, देहरादून-248001	चमोली
11.	श्री शम्भूनाथ सिंह सेठवाल, मकान नं०-189/1, नई बस्ती, ब्लॉक-सी, रेसकोर्स, देहरादून-248001	हरिद्वार
12.	श्री लवल कुमार वर्मा, 138/5, डी०एल० रोड, देहरादून-248001	रुद्रप्रयाग
13.	श्री कुलदीप नारायण, 70 अपर अद्योईवाला, विकास लोक, लेन नं०-3, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248001	पौड़ी गढ़वाल
14.	श्री अनिल कुमार कोरी, पश्चिमी राजीव नगर, घोडानाला, बिन्दुखत्ता, तहसील-लालकुआँ, नैनीताल-262402	पिथौरागढ़

विज्ञप्ति/नियुक्ति

08 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 422/XXX(4)/2017-04(3)/2017-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2015 के आधार पर चयनित एवं उनके पत्रांक 462/07/ई-2/CJ-JD/2015-16, दिनांक 16 मार्च, 2017 एवं पत्रांक 04/10/ई-2/CJ-JD/2015-16, दिनांक 06 अप्रैल, 2017 द्वारा की गई संस्तुति तथा इस सम्बन्ध में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 4880/XIII-d-1/Admin.A/2014, दिनांक 08 नवम्बर, 2017 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के

पद पर वेतनमान ₹ 27,700-770-33,090-920-40,450-1080-44,770 में, नियुक्त किये जाने तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परीक्षाकाल पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	नाम अभ्यर्थी	तैनाती स्थल
1	2	3
1.	कु० शिवानी नाहर, 08, दुर्गा विहार, मेजर विवेक गुप्ता मार्ग, नियर बल्लीवाला चौक, देहरादून-248001	ऊधमसिंह नगर

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

सिचाई विभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

17 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 1908/II(1)-2017-01(42)(430)/2012-नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं को वेतनमान लेवल 12, ₹ 78,800-2,08,200 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1.	राम सकल आर्य	वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी (विधि), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि० वि०, देहरादून
2.	प्रेम सिंह पंवार	अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्यमण्डल, उत्तरकाशी
3.	सुभाष चन्द्र	वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी (बजट), प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून
4.	संजय शुक्ल	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, हल्द्वानी (सम्बद्ध) [श्री त्रिभुवन सिंह, वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी के मुख्य अभि०, स्तर-2 पर सम्भावित पदोन्नति के उपरान्त पदस्थापना (माह जनवरी, 2018)]
5.	पुनीत कुमार मल्ल	अधीक्षण अभियन्ता, शोध मण्डल, रुड़की
6.	सुधीर कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर, प्रदेशीय अभियन्ता, प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की
7.	शंकर कुमार साहा	अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद, हरिद्वार
8.	संजीव कुमार श्रीवास्तव	अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्यमण्डल, नई टिहरी
9.	नवीन सिंघल	अधीक्षण अभियन्ता, परिकल्प मण्डल, रुड़की
10.	प्रमोद कुमार दीक्षित	अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्यमण्डल, पिथौरागढ़
11.	विजय कुमार पाण्डे	अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून

2. उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।
3. उक्त संस्तुत अभियन्ताओं की पदोन्नति ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या 22/एस०बी०/2016, श्री सुभाष चन्द्र बनाम राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

17 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 1910/॥(1)-2017-01(440)/2012-कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान ₹ 15,600-39,100, सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 6,600 (वर्तमान में लेवल-11, ₹ 67,700-2,06,700) में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक सर्वश्री

1. गणपति प्रसाद सिलवाल,
2. अतर सिंह विष्ट,
3. हरीश चन्द्र नौटियाल,
4. सुन्दर लाल कुड़ियाल।

2. उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।
3. उक्त पदोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 442/एस०बी०/2016, श्री विजयपाल एवं अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।
4. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग-1

कार्यालय आदेश

09 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 871/XX(1)-2017-3(20)2004-विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री मिश्री लाल, निरीक्षक (एम)/कार्यालय अधीक्षक शाखा, अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखण्ड को पुलिस उपाधीक्षक (एम), वेतनमान ₹ 15,600-39,100, सादृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400 (यथापुनरीक्षित) के पद पर एतद्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष अथवा अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, तक परीक्षाधीन रहेंगे।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

09 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1896/VII-2/471/उद्योग/2002—श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं/पदों पर "उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क")" सेवा नियमावली, 2017" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम-8(1) का प्रतिस्थापन:

उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 2017 के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 8(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:—

नियम	पदनाम	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
		वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8(1)	निदेशक, उद्योग एवं अपर निदेशक, उद्योग	(क) निदेशक, उद्योग एवं अपर निदेशक, उद्योग के पद के लिए: (एक) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष (दो) प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग — सदस्य (तीन) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग — सदस्य (चयन की कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी) (ख) संयुक्त निदेशक, उद्योग के पद के लिए: (एक) प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग— सदस्य (दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक या उसका कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सरकार के अपर सचिव स्तर से निम्न न हो — सदस्य (तीन) शासन द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी — सदस्य	(क) निदेशक, उद्योग के पद के लिए: (एक) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष (दो) प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य (तीन) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य (चयन की कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी) (ख) अपर निदेशक, उद्योग एवं संयुक्त निदेशक, उद्योग के पद के लिए: (एक) प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष (दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग या उनके द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट अधिकारी, जो राज्य सरकार के अपर सचिव स्तर से निम्न न हो — सदस्य (तीन) यथास्थिति महानिदेशक/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड — सदस्य
		(चार) निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड — सदस्य	

आज्ञा से,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1896/VII-2/471/Industry/2002, dated November 09, 2017 for general information.

NOTIFICATION

November 09, 2017

No. 1896/VII-2/471/Industry/2002--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to make the following rules with a view further to amend the Uttarakhand Industry (Senior Category "A") Service rules, 2017:

The Uttarakhand Industry (Senior Category 'A') (Amendment) Service Rules, 2017**1. Short title and commencement :**

- (1) These Rules may be called the Uttarakhand Industry (Senior Category 'A') (amendment) Service Rules, 2017.
- (2) It shall come in to force at once.

2. Amendment of sub-rule (1) of rule 8 :

In the Uttarakhand Industry (Senior Category "A") Service Rules, 2017, in sub-rule (1) of rule 8 of the existing rule set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely :

COLUMN 1	COLUMN 2
<i>Existing Rules</i>	<i>Rules as hereby substituted</i>
<p>(A) for the post of Director, Industry and Additional Director, Industry :</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Chief Secretary, Government of Uttarakhand --Chairman; (ii) Principal Secretary/Secretary, Micro, Small and Medium Industry Department -- Member; (iii) Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand -- Member <p>(the selection proceeding shall by the Personnel Department).</p> <p>(B) for the post of Joint Director, Industry :</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Principal Secretary/Secretary, Small and Medium Industry Department -- Member; (ii) Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand or his nominee, who is not below the rank of Additional Secretary -- Member; (iii) A officer of Scheduled Caste/Tribes nominated by Government of Uttarakhand -- Member; (iv) Director, Industry, Uttarakhand Government -- Member 	<p>(A) for the post of Director, Industry :</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Chief Secretary, Government of Uttarakhand --Chairman; (ii) Principal Secretary/Secretary, Micro, Small and Medium Industry Department -- Member; (iii) Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand -- Member <p>(the selection proceeding shall by the Personnel Department).</p> <p>(B) for the post of Additional Director and Joint Director, Industry :</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Principal Secretary/Secretary, Micro, Small and Medium Industry Department --Chairman; (ii) Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand or his nominated officer, who is not below the rank of Additional Secretary -- Member; (iii) Director General/Director, as the case may be Industry Uttarakhand Government -- Member

By Order,

MANISHA PANWAR,

Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 50 हिन्दी गजट/804-भाग 1-2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 25, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 10, 2017

No. 264/UHC/Admin.A/2017--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 422/XXX(4)/2017-04(03)/2017, dated 08.11.2017, Ms. Shivani Nahar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Sitarganj, District Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

CONFIRMATION

November 13, 2017

No. 265/UHC/Admin.A/2017--The following Judicial Officers shall be deemed to have been confirmed in Uttarakhand Higher Judicial Service, on their respective posts from the date of completion of their period of probation or extended period of probation, whichever is later:

1. Smt. Anjushree Juyal
2. Smt. Pritu Sharma
3. Sri Sujeet Kumar
4. Sri Mohammad Sultan
5. Sri Mahesh Chandra Kaushiwa
6. Smt. Shadab Bano
7. Sri Naseem Ahmad

NOTIFICATION

CONFIRMATION

November 13, 2017

No. 266/UHC/Admin.A/2017—The following Judicial Officers shall be deemed to have been confirmed in Uttarakhand Judicial Service, on their respective posts from the date of completion of their period of probation or extended period of probation, whichever is later:

1. Ms. Rinky Sahni
2. Ms. Shivani Pasbola
3. Sri Ravi Prakash
4. Sri Shahjad Ahmad Wahid
5. Ms. Akata Mishra
6. Sri Rajeev Dhavan
7. Mohd. Yaqoob
8. Ms. Chhavi Bansal
9. Ms. Ritika Semwal
10. Ms. Vibha Yadav
11. Sri Sanjay Singh
12. Sri Sayed Gufran
13. Ms. Indu Sharma
14. Sri Manoj Kumar Dwivedi
15. Smt. Niharika Mittal Gupta
16. Sri Harsh Yadav
17. Sri Ravi Shankar Mishra
18. Sri Sandip Kumar Tiwari
19. Smt. Seema Dungarakoti
20. Ms. Shachi Sharma
21. Ms. Sweta Pandey
22. Sri Abhishek Kumar Srivastava
23. Ms. Shweta Rana Chauhan
24. Sri Avinash Kumar Srivastava
25. Ms. Tricha Rawat
26. Sri Sachin Kumar
27. Ms. Lalita Singh
28. Ms. Arti Saroha
29. Sri Sanjeev Kumar
30. Ms. Simranjit Kaur
31. Sri Sandeep Singh Bhandari
32. Ms. Shama Nargis
33. Ms. Neha Kushawaha

34. Ms. Anita Kumari
35. Ms. Neha Qayyum
36. Sri Akram Ali
37. Sri Neeraj Kumar
38. Sri Ashok Kumar
39. Smt. Payal Singh

By Order of the Court,
Sd/-
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

NOTIFICATION

November 13, 2017

No. 267/UHC/XIV-a-4/Admin.A/2009--Sri Dharendra Bhatt, Additional Chief Judicial Magistrate, Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 24.10.2017 to 03.11.2017 with permission to suffix 04.11.2017 and 05.11.2017 as Kartik Purnima and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

November 15, 2017

No. 268/UHC/XIV-a-50/Admin.A/2012--Ms. Neha Kushawaha, Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 18.09.2017 to 28.09.2017 with permission to prefix 17.09.2017 as Sunday holiday and suffix 29.09.2017 to 30.09.2017 as Dussehra, 01.10.2017 as Sunday and 02.10.2017 as Gandhi Jayanti holidays respectively.

NOTIFICATION

November 18, 2017

No. 270/UHC/XIV-a/32/Admin.A/2015--Ms. Meenal Chawla, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora is hereby sanctioned medical leave for 25 days w.e.f. 05.10.2017 to 29.10.2017.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़**कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र** **$\frac{16}{24}$ अक्टूबर, 2017 ई0**

पत्रांक 513/1-9-2017-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की अधिसूचना संख्या-254/यू0एच0सी0/एडमिन. ए/2017, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के अनुपालन में मेरे द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 16.10.2017 के अपराह्न में ग्रहण किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 (अस्पष्ट)

प्र0 जनपद न्यायाधीश,

पिथौरागढ़।

अनिल कुमार कोरी,

सिविल जज (जूनियर डिवीजन),

गंगोलीहाट,

जिला पिथौरागढ़।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड**(विधि अनुभाग)****15 नवम्बर, 2017 ई0**

समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 3912/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि-अनुभाग/17-18/देहरादून-उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 913/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 915/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 916/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 917/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 918/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 एवं 919/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, समदिनांकित 10 नवम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः माल, जिनका विवरण अधिसूचना के निर्मित तालिका के स्तम्भ 2 में है, विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन, राज्य के भीतर आपूर्ति पर 2.5 प्रतिशत की राज्य कर की दर अधिसूचित करने; माल की पूर्तियों को समझे गये निर्यातों के रूप में अधिसूचित करने; अधिसूचना संख्या 914, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के संदर्भ में प्रतिदाय के दावा करने हेतु पूर्तियों के पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित करने; निर्यात के लिए एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर योग्य वस्तुओं पर, राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगने वाले राज्य कर, जो 0.05 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक है, पर सशर्त छूट प्रदान करने; माह अगस्त व माह सितम्बर, 2017 हेतु जीएसटीआर-3ख दाखिल न किये जाने पर विलम्ब शुल्क माफ किये जाने; अधिसूचना संख्या 531, दिनांक 29 जून, 2017 में संशोधन करने एवं धारा 51 प्रवृत्त किये जाने संबंधी अधिसूचित किये गये हैं।

उपरोक्त अधिसूचनाएँ, इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 913/2017/9(120)/XXVII(8)/2017-चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, माल जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है तथा जो उक्त तालिका के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अन्तर्गत आता है, पर नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन, राज्य के भीतर आपूर्ति पर 2.5 प्रतिशत की राज्य कर की दर अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं०	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखी गई खाद्य निर्मितियाँ।	यदि खाद्य निर्मितियों का प्रदायक ऐसे किसी अधिकारी से, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है या संबंधित राज्य सरकार में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी खाद्य निर्मितियाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख से पाँच मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अतिरिक्त अवधि के भीतर जो इस निमित्त केन्द्रीय कर के अधिकारिता आयुक्त या राज्य कर के अधिकारिता आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अनुज्ञात की जाएगी, वितरित कर दी गई है।

स्पष्टीकरण-(एक) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष" "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा;

(दो) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अन्तर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 913/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated November 10, 2017 for general information.

NOTIFICATION

November 10, 2017

No. 913/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the State tax rate of 2.5 percent on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), subject to the condition specified in column (4) of the Table below, namely:--

Table

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government.	When the supplier of such food preparations produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government concerned to the effect that such food preparations have been distributed free to the economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or the State Government concerned, within a period of five months from the date of supply of such goods or within such further period as the Jurisdictional Commissioner of the Central tax or Jurisdictional Commissioner of the State tax, as the case may be, may allow in this regard.

Explanation :

- (i) In this notification, "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
 - (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
2. This notification shall deemed to come into force from 18th day of October, 2017.

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध माल की पूर्तियों को समझे गए निर्यातों के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं०	पूर्ति का वर्णन
(1)	(2)
1.	अग्रिम प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
2.	निर्यात संवर्धन पूँजी माल प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पूँजी माल की पूर्ति
3.	निर्यातोन्मुख यूनिट को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
4.	अग्रिम प्राधिकार के प्रति अधिसूचना सं० 50/2017—सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 (यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट किसी बैंक या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा स्वर्ण की पूर्ति

स्पष्टीकरण:—

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

1. "अग्रिम प्राधिकार" से आयात के लिए या भौतिक निर्यातों के लिए पूर्व आयात आधार पर इनपुट के घरेलू उपापन के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है;
2. निर्यात संवर्धन पूँजी माल प्राधिकार से भौतिक निर्यातों के लिए पूँजी माल के लिए आयात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 5 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है;
3. "निर्यातोन्मुख यूनिट" से विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित निर्यातोन्मुख यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अभिप्रेत है।

यह अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated November 10, 2017 for general information.

NOTIFICATION

November 10, 2017

No. 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 147 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the supplies of goods listed in column (2) of the Table below as deemed exports, namely :--

Table

S. No.	Description of supply
(1)	(2)
1.	Supply of goods by a registered person against Advance Authorisation
2.	Supply of capital goods by a registered person against Export Promotion Capital Goods Authorisation
3.	Supply of goods by a registered person to Export Oriented Unit
4.	Supply of gold by a bank or Public Sector Undertaking specified in the notification No. 50/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017 (as amended) against Advance Authorisation.

Explanation :

For the purposes of this notification :

1. "Advance Authorisation" means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 4 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import or domestic procurement of inputs on pre-import basis for physical exports.
2. Export Promotion Capital Goods Authorisation means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import of capital goods for physical exports.
3. "Export Oriented Unit" means an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit approved in accordance with the provisions of Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2015-20.

This Notification shall be deemed to come into force from the 18th day of October, 2017.

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 915/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खण्ड (छ) सपठित उत्तराखण्ड शासन, वित्त, अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को, अग्रसारित दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित ऐसे साक्ष्य के रूप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझी गई निर्यात पूर्तियों के पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं0	साक्ष्य
(1)	(2)
1.	यथास्थिति, अग्रिम प्राधिकारधारक या निर्यात संवर्धन पूँजी माल प्राधिकारधारक का अधिकारिता वाला कर अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति, कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियाँ उक्त अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूँजी माल प्राधिकारधारक द्वारा प्राप्त हो गई हैं या प्राप्तिकर्ता निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित ऐसा कर बीजक, जिसके अधीन ऐसी पूर्तियाँ पूर्तिकर्ता द्वारा की गई हैं, कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियाँ उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं, कि एक प्रति।
2.	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि ऐसी पूर्तियों पर कोई इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उसके द्वारा नहीं लिया गया है।
3.	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि वह ऐसी पूर्तियों की बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 915/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated November 10, 2017 for general information.

NOTIFICATION

November 10, 2017

No. 915/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-rule (2) of rule 89 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 read with Notification No. 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated November 10, 2017 of Government of Uttarakhand, Finance Section-8, the Governor, is pleased to notify the following, as detailed in column (2) of the Table below, as evidences which are required to be produced by the supplier of deemed export supplies for claiming refund, namely :--

Table

S. No.	Evidence
(1)	(2)
1.	Acknowledgment by the jurisdictional Tax officer of the Advance Authorisation holder or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, as the case may be, that the said deemed export supplies have been received by the said Advance Authorisation or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, or a copy of the tax invoice under which such supplies have been made by the supplier, duly signed by the recipient Export Oriented Unit that said deemed export supplies have been received by it.
2.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that no input tax credit on such supplies has been availed of by him.
3.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that he shall not claim the refund in respect of such supplies and the supplier may claim the refund.

This Notification shall be deemed to come into force from the 18th day of October, 2017.

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 916/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (एतस्मिन् पश्चात् जिसे इस अधिसूचना में, उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, निर्यात के लिए एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर योग्य वस्तुओं (एतस्मिन् पश्चात् जिसे इस अधिनियम में उक्त वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) पर राज्य के भीतर आपूर्ति पर, उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत इन पर लगने वाले राज्य कर, जो 0.05 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक है, पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा—

- (i) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, पंजीकृत प्राप्तकर्ता को टैक्स इनवॉयस पर वस्तुओं की आपूर्ति करेगा;
- (ii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर इनवाइस जारी किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उक्त वस्तुओं का निर्यात करेगा;
- (iii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की माल एवं सेवाकर की पहचान संख्या एवं उक्त वस्तुओं के संबंध में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी टैक्स इनवाइस संख्या शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो, में दर्शायेगा;
- (iv) पंजीकृत प्राप्तकर्ता का निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मद संबंधी बोर्ड द्वारा पंजीकरण किया जायेगा;
- (v) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, रियायती दर पर वस्तुएँ खरीदने के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को आदेश जारी करेगा तथा इसकी एक प्रति पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;
- (vi) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के स्थान से उक्त वस्तुओं को सीधे—
 - (क) बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर जहाँ से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, ले जाएगा; या
 - (ख) किसी पंजीकृत वेयर हाउस पर जहाँ से उक्त वस्तुओं को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जाएगा, जहाँ से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है।
- (vii) यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता, कई पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त हुई आपूर्ति को समेकित करके फिर निर्यात करना चाहता है तो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की वस्तुएँ, पंजीकृत वेयर हाउस को भिजवाई जायेगी तथा समेकन के पश्चात् पंजीकृत प्राप्तकर्ता वस्तुओं को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जायेगा, जहाँ से उनका निर्यात किया जाएगा;
- (viii) इस मामले में शर्त (vii) में बताई गई स्थिति में, पंजीकृत प्राप्तकर्ता, टैक्स इनवायस पर वस्तुओं की प्राप्ति पृष्ठांकित करेगा और वेयर हाउस ऑपरेटर से पंजीकृत वेयर हाउस में वस्तुओं की प्राप्ति की आवृत्ति प्राप्त करेगा तथा पृष्ठांकित टैक्स इनवाइस और वेयर हाउस ऑपरेटर की पावती, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को तथा ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;
- (ix) जब वस्तुएँ निर्यात कर दी जाती हैं तो पंजीकृत प्राप्तकर्ता, शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, जिसमें जीएसटीआईएन का ब्यौरा और पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की टैक्स इनवाइस अंकित हो तथा इसके साथ एक्सपोर्ट जनरल मैनीफैस्ट का सुबूत या पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को और ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त टैक्स अधिकारी को दायर की गई निर्यात रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायेगा।

2. यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता उक्त वस्तु के निर्यात में कर बीजक के जारी होने के 90 दिनों के भीतर असफल रहता है तो उक्त संदर्भित छूट के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पात्र नहीं होगा।

3. यह अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 916/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated November 10, 2017 for general information.

NOTIFICATION

November 10, 2017

No. 916/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to exempt the intra-State supply of taxable goods (hereafter in this notification referred to as "the said goods") by a registered supplier to a registered recipient for export, from so much of the State tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate of 0.05 per cent, subject to fulfillment of the following conditions, namely :

- (i) the registered supplier shall supply the goods to the registered recipient on a tax invoice;
- (ii) the registered recipient shall export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of a tax invoice by the registered supplier;
- (iii) the registered recipient shall indicate the Goods and Services Tax Identification Number of the registered supplier and the tax invoice number issued by the registered supplier in respect of the said goods in the shipping bill or bill of export, as the case may be;
- (iv) the registered recipient shall be registered with an Export Promotion Council or a Commodity Board recognised by the Department of Commerce;
- (v) the registered recipient shall place an order on registered supplier for procuring goods at concessional rate and a copy of the same shall also be provided to the jurisdictional tax officer of the registered supplier;
- (vi) the registered recipient shall move the said goods from place of registered supplier :
 - (a) directly to the Port, Inland Container Depot, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported; or
 - (b) directly to a registered warehouse from where the said goods shall be move to the Port, Inland Container Depot, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported;
- (vii) if the registered recipient intends to aggregate supplies from multiple registered suppliers and then export, the goods from each registered supplier shall move to a registered warehouse and after aggregation, the registered recipient shall move goods to the Port, Inland Container Depot, Airport or Land Customs Station from where they shall be exported;
- (viii) in case of situation referred to in condition (vii), the registered recipient shall endorse receipt of goods on the tax invoice and also obtain acknowledgement of receipt of goods in the registered warehouse from the warehouse operator and the endorsed tax invoice and the acknowledgment of the warehouse operator shall be provided to the registered supplier as well as to the jurisdictional tax officer of such supplier; and
- (ix) when goods have been exported, the registered recipient shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) and tax invoice of the registered supplier along with proof of export general manifest or export report having been filed to the registered supplier as well as jurisdictional tax officer of such supplier.

2. The registered supplier shall not be eligible for the above mentioned exemption if the registered recipient fails to export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of tax invoice.

3. This Notification shall be deemed to come into force from the 23rd day of October, 2017.

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 917/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर 3-ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस का अधित्यजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 917/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated November 10, 2017 for general information.

NOTIFICATION

November 10, 2017

No. 917/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017(06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor, is pleased to allow to waive the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of August, 2017 and September, 2017 by the due date.

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 918/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06, वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (5) संपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं0 531/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में उपवाक्य (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जायेगा;
“(तीन) हाउस कीपिंग के माध्यम से दी जाने वाल सेवाओं जैसे कि पलंबिंग, कारपेंटरिंग आदि, सिवाय वहाँ, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।”
2. यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 918/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated November 10, 2017 for general information.

NOTIFICATION

November 10, 2017

No. 918/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017) read with section 21 of the General Clauses Act, 1904 (Act no. 01 of 1904), on the recommendations of the Council, the Governor, is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 531/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 29th June, 2017, namely:

1. In the said notification, in the first paragraph, after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely :
“(iii) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc., except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017".
2. This notification shall deemed to come into force from the 22nd day of August, 2017.

By order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिशनर, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल
कार्यालय आदेश

03 नवम्बर, 2017 ई०
06

पत्र संख्या 1050/सा0प्रशा0/का0आ0/लाइ0 निल0/2017-18—निम्नलिखित चालक के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह की अवधि हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा की दृष्टिगत ओवर लोडिंग, शराब पीकर वाहन संचालन, ओवर स्पीड आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:—

क्र० सं०	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या एवं प्रकार व वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	लाइसेन्स निरस्त/निलम्बन की अवधि
1.	श्री चण्डी प्रसाद पुत्र श्री आशाराम, निवासी म० नं० 246, ग्राम सिताबपुर सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल	UK-1520040025149, LMV(NT), TRANS (TR), PSVBUS (TR), only 27.10.2016 to 26.10.2019	प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	ऑटो रिक्शा के चालक कक्ष में दो सवारी बैठाये जाने पर	03.11.2017 से 02.12.2017

रावत सिंह,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार।

कार्यालय संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून विज्ञप्ति

13 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5119/रा०प०-3-चक०सं०/2017-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 673/XVIII(III)/2016-03(07)/2016, दिनांक 30.10.2017 से प्राप्त शासन की अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की, हरिद्वार, लक्सर एवं भगवानपुर के निम्नलिखित 07 ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है:-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	परगना	तहसील	जनपद
1.	बेलडा मुस्तकम	रुड़की	रुड़की	हरिद्वार
2.	टोडा कल्याणपुर अह०	रुड़की	रुड़की	हरिद्वार
3.	जठेडी	मंगलौर	रुड़की	हरिद्वार
4.	रायपुर	ज्वालापुर	लक्सर	हरिद्वार
5.	लालवाला मजवता	भगवानपुर	भगवानपुर	हरिद्वार
6.	बादशाहपुर	रुड़की	हरिद्वार	हरिद्वार
7.	टान्डा बन्जारा	रुड़की	हरिद्वार	हरिद्वार

सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
संचालक, चकबन्दी,
उत्तराखण्ड-देहरादून।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4437 लाइसेंस/2016-17-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.06.2017 को वाहन संख्या UK07BM-4237, मोटरसाइकिल का चालान, चालक द्वारा खतरनाक तरीके से वाहन संचालन के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री अंकित असवाल S/o श्री गजेन्द्र सिंह, चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0920170025834, जो टिहरी कार्यालय द्वारा 22.04.2017 के लिए वाहन संचालन करने हेतु जारी किया गया है तथा 21.04.2037 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4438 लाइसेंस/2016-17-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.06.2017 को वाहन संख्या BP-6PC-6489, मोटर कार का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री विकास कुमार S/o श्री दिनेश कुमार, चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-1120090007079, जो 16.07.2009 को कार्यालय द्वारा 15.07.2029 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4439 लाइसेंस/2016-17-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 11.07.2017 को वाहन संख्या यू०के०-०७टीए-३२७५, मोटर कार का चालान, चालक द्वारा वाहन संचालन निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वाहन चालक श्री रमेश असवाल S/o श्री गारेख सिंह, चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू०ए०-०७१९९५०१३०४६२० जो इस कार्यालय द्वारा ०८.०९.१९९५ के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा ०१.११.२०२० तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता २९.११.२०१९ तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4440 लाइसेंस/2016-17-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.06.2017 को वाहन संख्या यू०ए०-०७एके-६४८४, मोटर साइकिल का चालान, चालक द्वारा वाहन संचालन करते समय मोबाइल का प्रयोग करने के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वाहन चालक श्री मेहरबान अली पुत्र श्री इमरान अली, चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू०ए०-०७२००७००२६१०४, जो इस कार्यालय द्वारा ०३.११.२००७ के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा ०२.११.२०२७ तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता २९.११.२०१९ तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4441/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.07.2017 को वाहन संख्या यू०के०-०७बीपी-3276, मोटर साइकिल वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मौ० आसिफ पुत्र श्री अब्दुल कयाम की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू०ए०-०७२०१५००१०१५०, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2035 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4442/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.06.2017 को वाहन संख्या यू०के०-०७बीडब्लू-0843, मोटर साइकिल वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री राजेश कुमार पुत्र श्री भगवानदीन मौर्य की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू०पी०-20150005706, जो कि अम्बेडकर नगर कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 02.05.2015 से 01.05.2035 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4443 लाइसेंस/2016-17-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.07.2017 को वाहन संख्या यू०के०-०८टीए-5359, मोटर कार का चालान, चालक द्वारा वाहन निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री विपिन कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर, चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू०के०-०८२००६००१४५०८, जो सहायक सम्भागीय कार्यालय, हरिद्वार द्वारा 06.12.2006 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा 30.11.2023 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4444/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.07.2017 को वाहन संख्या DL9CAD-3114, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो० फो० का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री राहुलचन्द S/o श्री कपूर चन्द की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1020120003415, जो कि कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 21.03.2012 से 20.03.2032 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4445/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.06.2017 को वाहन संख्या यू०के०-07 जेड-4868, मोटर साइकिल वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री आकाश पुत्र श्री डी० पी० प्रभाकर की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू०ए०-0720090078393, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 12.06.2009 से 27.05.2021 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4446 लाइसेंस/2016-17-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.04.2017 को वाहन संख्या यू०के०-07बी-7334, मोटर साइकिल का चालान, चालक द्वारा वाहन रेड लाइट जम्प करने के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री विजेन्द्रलाल पुत्र श्री उमालाल, चालन अनुज्ञप्ति सं० यू०ए०-0720120201734, जो इस कार्यालय द्वारा 29.03.2012 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा 01.03.2027 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 12 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4447 लाइसेंस/2016-17-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.07.2017 को वाहन संख्या यू०के०-०७बीएम-3205, मोटर साइकिल का चालान, चालक द्वारा वाहन संचालन करते समय, मोबाइल फोन का प्रयोग करने के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वाहन चालक श्री सोमिल पुत्र श्री बलवन्त सिंह के चालन अनुज्ञप्ति सं० यू०के०-०४२००९००१४०१९, जो कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा 23.03.2009 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा 22.03.2029 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 25 के उपनियम 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4448 लाइसेंस/2016-17-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 28.05.2017 को वाहन संख्या डीएल 10 सीएच-7441, मोटर कार का चालान, चालक द्वारा वाहन संचालन निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री दिलीप दास पुत्र श्री बाको दास के चालन अनुज्ञप्ति सं० पी०७९७०८०१९४, जो कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा 23.03.2009 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा 22.03.2029 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4449/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.07.2017 को वाहन संख्या यू०के०-०७सीबी-2513, मोटर कार वाहन का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री जीवन लाल पुत्र श्री एस० चन्द की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू०के०-०७१९८७०२२८७८०, जो इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 01.01.2012 से 31.10.2017 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 01.01.2015 से 31.10.2018 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4450/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.07.2017 को वाहन संख्या यू0के0-07पी-1021, मोटर साइकिल वाहन का चालान, चालक द्वारा रेड लाइट जम्प करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री हिमांशु शर्मा पुत्र श्री एस0 पी0 शर्मा की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0ए0-0720110175979, जो इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 09.09.2011 से 07.01.2023 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5215/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 27.07.2017 को वाहन संख्या MH26AK-4963, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मनमोहन सिंह S/o श्रीपति नारायण सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या MP4IN-2012-0111452, जो कि मध्य प्रदेश कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 09.09.2012 से 30.09.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5216/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.07.2017 को वाहन संख्या UK07CB-2555, ट्रक वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri M.R. Lal Bahadur S/o Sri Tul Bahadur की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-0719980147791, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 01.07.1998 से 19.02.2018 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5217/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.07.2017 को वाहन संख्या UK07BR-9505, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vivek Ale S/o Sri M. S. Ale की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720020145640, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 09.10.2002 से 08.10.2022 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5218/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 27.07.2017 को वाहन संख्या UK07BR-1438, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light Jump के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री रविन्द्र बिष्ट S/o श्री आनन्द बिष्ट की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0920140011077, जो कि टिहरी कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 09.04.2014 से 08.04.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5219/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.07.2017 को वाहन संख्या UK16A-419, Car वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sunder Lal S/o Sri Sohan Lal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0719960160547, जो कि विकासनगर कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 26.05.2017 से 21.10.2026 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 28.05.2017 से 27.05.2020 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5220/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.06.2017 को वाहन संख्या UK07BV-0964, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो० फो० का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सचिन कुमार चौहान S/o श्री वी० एस० चौहान की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720110174742, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 02.09.2011 से 01.09.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5221/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 10.08.2017 को वाहन संख्या UP14AV-4623, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Jitendra S/o Ved Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या J3369/MZN/2001, जो कि MZN (U.P.) कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 20.02.2001 से 19.02.2021 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5223/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 26.07.2017 को वाहन संख्या UK07AS-9691, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री उमेश सिंह नेगी S/o श्री टी० एस० नेगी की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-072008004286, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 08.04.2008 से 07.04.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5224/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 11.07.2017 को वाहन संख्या UK07CB1383, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Amit Sharma (Over Load) के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Amit Sharma S/o Sri Shyam Sharma की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720020183821, जो कि कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 13.11.2002 से 12.11.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 17.05.2017 से 16.05.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5226/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 29.06.2017 को वाहन संख्या UK07AN-8730, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Use of Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Jitender Semwal S/o Sri G. D. Semwal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 81427/Dun/05, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 21.07.2005 से 14.09.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5228/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.06.2017 को वाहन संख्या HRSIH-6564, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री जतिन S/o श्री अनिल कुमार की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 030812245/418/2003, जो कि Noida कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 04.08.2003 से 03.08.2023 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5227/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 15.06.2017 को वाहन संख्या UK17C-3355, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sukhdev Singh S/o Sri Naresh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0820080002445, जो कि Haridwar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 26.06.2008 से 25.06.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5228/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.06.2017 को वाहन संख्या MD2A36PYCHCM2017, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Use of Mobile & without Helmet के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Ritik Bhardwaj S/o Sri Neeraj Sharma की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP1420160009159, जो कि Ghaziabad कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 11.03.2016 से 10.03.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5229/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.06.2017 को वाहन संख्या UK07AL-5387, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय शराब पीकर वाहन चलाना के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Jogendra Singh S/o Sri Kulwant Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK072014029853, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 01.05.2014 से 06.03.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5230/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.06.2017 को वाहन संख्या UK7U-2528....., वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय खतरनाक तरीके से वाहन चलाना के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालककी चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720160016315, जो कि कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 06.04.2016 से 05.04.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांकसे तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 5231/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.06.2017 को वाहन संख्या UK07BJ-6969, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vibhav Gupta S/o Sri Sunny Gupta की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720060106475, जो कि कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 26.04.2006 से 25.04.2026 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांकसे तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,

मोटर वाहन विभाग,

देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, 16 दिसम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 25, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला रुधमसिंह नगर

10 सितम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 47/6/यूजर चार्ज नियमावली प्रकाशन/2016-17-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न उपविधि जनता की आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशित की जाती है, जिस किसी को भी इस संबंध में आपत्ति/सुझाव देने हों, लिखित में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर नगर पंचायत, नानकमत्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, उपविधि का अवलोकन नगरपालिका परिषद् कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है, समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 सूची 1अ के खण्ड (घ) एवं भारत का राजपत्र नई दिल्ली 25.09.2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को नियमित करते हुए उपयोग शुल्क (यूजर चार्ज) की उपविधि बनाई जाती है।

अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम-इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और हथालन नियम, 2000 के अन्तर्गत उपयोग शुल्क (यूजर चार्ज) नियम, 2016 होगा।
2. प्रारम्भ-जैसा इन नियमों अन्यथा उपबंधित है, उसके अतिरिक्त में राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू/प्रवृत्त होंगे।
3. लागू होना-ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रह पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के संचालन एवं रख-रखाव के लिये होगा। म्यूनिसिपल एक्ट, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम भारत का राजपत्र दिनांक 25.09.2000 के प्राविधानों पर निम्न उपविधियों व शुल्क आरोपण किये जाने हेतु आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशित की जाती है। जिस किसी को भी इस संबंध में आपत्ति/सुझाव देने हों लिखित में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर नगर पंचायत, नानकमत्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उपविधि का अवलोकन नगर पंचायत, नानकमत्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी आपत्ति/सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298अ (घ) एवं भारत का राजपत्र नई दिल्ली 25.09.2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को।

उपविधि नियमावली

1. यह उपविधि, नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर के सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन योजना के संचालन एवं रख-रखाव हेतु उपभोग शुल्क यूजर चार्ज उपविधि, 2016 कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर के सीमान्तर्गत प्रभावी होगी।

परिभाषा

1. नगर पंचायत से तात्पर्य, नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर से है।
2. अध्यक्ष, नगर पंचायत का तात्पर्य, अध्यक्ष, नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर से है।
3. अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर से है।
4. स्वच्छता समिति से तात्पर्य, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा गठित मोहल्ला स्वच्छता समितियों से है।

उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) शुल्क सूची:

1. प्रतिपरिवार/घर	₹ 30.00 प्रति माह।
2. बाजार क्षेत्र/हाट बाजार प्रति दुकान	₹ 50.00 प्रति माह।
3. मलीन बस्ती प्रति घर	₹ 20.00 प्रति माह।
4. होटल प्रति रुम	₹ 100.00 प्रति माह।
5. भोजनालय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थान और संस्थाएँ	₹ 75.00 प्रति माह।
6. निकटवर्ती मिल/फैक्ट्री, जो अपने अपशिष्टों को नगर सीमा से ले जाते हैं	₹ 6,000.00 प्रति माह।
7. सीमान्तर्गत के मिल/फैक्ट्री	₹ 600.00 प्रति माह।
8. अन्य व्यवसाय	₹ 150.00 प्रति माह।

शुल्क वसूली

1. नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति के द्वारा निर्धारित रसीद दी जायेगी।
2. नियत समय के अन्दर शुल्क यूजर चार्ज भुगतान न करने पर अवेश राशि की वसूली भू-राजस्व की माँति वसूली की जायेगी।
3. शुल्क वसूली हेतु नगर पंचायत, नानकमत्ता क्रियान्वयन संस्था निर्धारित प्रारूप पर माँग वसूली रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें प्रति माह/प्रतिदिन अथवा नगर पंचायत संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा समय-समय पर जनसुविधानुसार शुल्क वसूली की जायेगी। वार्षिक शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में एक मुस्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। उपभोग शुल्क एवं दण्ड वसूलने हेतु नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर के अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत, नानकमत्ता द्वारा अधिकृत क्रियान्वित करने वाली संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समितियाँ अधिकृत होगी।
4. प्रतिमाह/प्रतिदिन दैनिक आय की संलग्न प्रारूप का सत्यापन नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा।
5. उपभोग शुल्क वसूली अनुसूची में समय-समय पर जनसुविधानुसार नियमों में परिवर्तन का अधिकार नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर के बोर्ड में निहित है।

शास्ति/दण्ड

नगर पंचायत, नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग शुल्क नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त व्यवस्था के तहत कार्यवाही/जुर्माना/अर्थदण्ड, जो ₹ 1,000.00 तक होगा। यदि निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है तो इस धनराशि के अतिरिक्त ₹ 50.00 प्रतिदिन दण्ड देय होगा। यदि उपभोक्ता कूड़ा अलग-अलग डिब्बों में पृथक्कीकरण कर नहीं रखता है तो यूजर चार्जज दोगुने देय होंगे।

सरिता राणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, नानकमत्ता
(ऊधमसिंह नगर)।

ह0 (अस्पष्ट)
प्रभारी अधिकारी,
नगर पंचायत, नानकमत्ता
(ऊधमसिंह नगर)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/804-भाग 8-2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।